जनसत्ता

हार और हताशा

चुनाव नतीजों के बाद हारे हुए दल अपनी कमजोरियों की समीक्षा करते ही हैं। जिन दलों को उम्मीद से कम सीटें मिलती हैं, वे भी अपनी रणनीति पर मंथन करते हैं। फिर वे अगले चुनावों के लिए नए ढंग से मैदान में उतरने का साहस भरते हैं। पर इस लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जैसी हताशा विपक्षी दलों में नजर आ रही है, वह उनके साहस खो देने का संकेत देती है। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस हार से इस कदर निराश हुए कि उन्होंने पद छोड़ने की पेशकश कर दी। पार्टी कार्यकर्ता उन्हें मनाने में जुटे हैं, पर वे अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि वे अब अपने पद पर नहीं रहना चाहतीं। दूसरे दलों में भी इसी तरह की निराशा नजर आ रही है। दरअसल, इस लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को उम्मीद थी कि वे भाजपा और उसके सहयोगी दलों को सत्ता तक पहुंचने से रोकने में सफल होंगे। वे भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए काफी समय से एकजुटता दिखा रहे थे, चुनाव में कई राज्यों में गठबंधन करके मैदान में उतरे थे, पर भाजपा ने अपनी पहली पारी से भी अधिक सीटें हासिल की और विपक्ष को बुरी तरह धूल चटा दी।

हालांकि ऐसी हार-जीत पहली बार नहीं हुई है। मगर इस बार भाजपा की जीत विपक्षी दलों को इसलिए नहीं पच पा रही कि उन्हें अंदाजा था कि लोग पिछली सरकार के कामकाज के तरीके और उसके अनेक फैसलों से नाराज थे। उन्हें भाजपा को ऐसे समर्थन की उम्मीद नहीं थी। पिछले तीन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली कामयाबी से भी ऐसे ही संकेत मिले थे। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह था और उन्होंने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उनकी सभाओं में भीड़ भी नजर आती थी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा के उभार को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी घेरेबंदी कर रखी थी, पर उसे अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में पार्टी का मुखिया हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, तो उसका बड़प्पन माना जाता है। मगर राहुल गांधी ने इस हार को सहज ढंग से स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर कह दिया कि उन्हें अपने बेटों की चिंता अधिक थी, पार्टी की नहीं। इससे स्वाभाविक ही पार्टी में खलबली है।

कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। इससे पार पाने के मकसद से ही करीब पंद्रह साल पहले पार्टी के बुराड़ी अधिवेशन में राहुल गांधी ने महासचिव बनने के बाद अपना प्रस्ताव रखा था कि चुनावों में टिकट प्रत्याशी के कामकाज और जमीनी पकड़ को देखते हुए दिया जाना चाहिए, न कि परिवार के आधार पर। मगर वह प्रस्ताव पार्टी के भीतर चुपके से दफन कर दिया गया। यहां तक कि जब राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बने तब भी वे अपने प्रस्ताव को याद नहीं रख पाए, अपने वरिष्ठ नेताओं को उसके लिए मना नहीं पाए। अब उनके पद छोड़ने से पार्टी की स्थिति सुधर जाएगी, दावा नहीं किया जा सकता। इससे भाजपा को और लाभ मिलेगा, जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा भी। इसलिए अगर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों में इसी तरह हार से उपजी हताशा बनी रही, तो वह उन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित होगा।

आग के ठिकाने

सूरत की एक इमारत में लगी आग और उसमें झुलस कर तेईस से अधिक बच्चों का दम तोड़ देना कई सवाल खड़े करता है। आग बिजली के ट्रांसफार्मर के अचानक जल उठने की वजह से लगी। उस व्यावसायिक इमारत की चौथी मंजिल पर टिन की छत में कोचिंग कक्षाएं चल रही थीं। उसमें पढ़ रहे बच्चों को भागने का रास्ता नहीं मिला तो वे सीधा कूदने लगे। इस वजह से कई बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ज्यादातर बच्चों की जान दम घुटने से गई। ट्रांसफार्मर में लगी आग ने इतनी तेजी से व्यावसायिक इमारत की ऊपरी मंजिलों को अपनी जद में ले लिया कि वहां मौजूद लोग बचाव संबंधी उपायों के बारे में सोच भी नहीं पाए। जिस मंजिल पर कोचिंग कक्षाएं चल रही थीं, वहां से उतरने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां बनी थीं, जो आग में जल कर राख हो गईं और बच्चों को उतरने का कोई रास्ता ही नहीं मिल पाया। देश में ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं, पर उनसे कोई सबक लेना शायद कभी जरूरी नहीं समझा जाता। कोई बड़ी घटना हो जाने के बाद प्रशासन हरकत में आता है और फिर अपनी गलतियों को ढकने में जुट जाता है।

यह एक आम और जैसे सर्वस्वीकृत प्रवृत्ति बन चुकी है कि सार्वजनिक और व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन और आपातकालीन उपायों पर ध्यान देना, उनसे जुड़े नियम-कायदों का पालन करना जरूरी नहीं समझा जाता। इन नियमों का पालन कराने वाला महकमा भी अपनी आंखें मूंदे रखता है। अक्सर बिजली के तारों या फिर ट्रांसफार्मर से उठने वाली चिनगारी से भयानक हादसे हो जाते हैं। मगर हैरानी की बात है कि उसे लेकर सुरक्षा उपाय नहीं जुटाए जाते। उपहार सिनेमा अग्निकांड के बाद सख्ती बरतते हुए हर भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक और व्यावसायिक भवन में स्वचालित अग्निशमन उपकरण लगाना जरूरी कर दिया गया। मगर भवनों की व्यावसायिक मंजूरी लेने की गरज से भले ऐसे उपाय कर दिए जाते हैं, पर ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि उनके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता और वे उपकरण सड़ी-गली हालत में बस दिखावे के लिए पड़े रहते हैं। सूरत की जिस इमारत में आग लगी, अगर स्वचालित अग्निशमन व्यवस्था होती, तो इतना बड़ा हादसा शायद न हो पाता। इतने बच्चों की जान चली जाने के बाद प्रशासन सख्ती बरतने का दम भर रहा है, तो उसका क्या फायदा। उसे पहले ही इस मसले पर तत्पर रहना चाहिए था।

निजी व्यावसायिक भवनों में एक प्रवृत्ति यह भी आम है कि उनमें अधिक से अधिक जगह का उपयोग करने की कोशिश की जाती है। इसके चलते निकास आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं की जाती। इसी प्रवृत्ति का नतीजा है कि छतों आदि का भी अनधिकृत रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जिस कोचिंग के बच्चे मारे गए, वह भी इसी तरह चलाई जा रही थी। कोचिंग संस्थानों का चलन पिछले कुछ सालों में इस कदर बढ़ा है कि छोटी से छोटी जगहों, संकरी गलियों, टिन-टप्पर वाली छतों में भी चलाए जाने लगे हैं। चूंकि कोचिंग खोलने के लिए कोई नियम-कायदा नहीं है, किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है, इसलिए सुरक्षा उपायों, सुविधाओं वगैरह की न तो उन पर कोई बंदिश है और न वे खुद इसकी परवाह करते हैं। समझना मुश्किल है कि इस तरह लोगों की जान की कीमत पर क्यों किसी व्यावसायिक गतिविधि को चलते रहने देना चाहिए!

कल्पमेधा

जो कमजोरों पर दया नहीं करता है,
उसे अपने से ताकतवरों के
अत्याचार सहने पड़ेंगे।
– शेख सादी

बेपटरी होती शिक्षा

अरविंद कुमार सिंह

पिछले दिनों उद्योग संगठन एसोचैम के एक अध्ययन में कहा गया कि शिक्षा में सुधार की रफ्तार अगर ऐसी ही रही, तो भारत को विकसित देशों की तरह अपनी शिक्षा के स्तर को शीर्ष पर ले जाने में एक सौ छब्बीस साल का समय लगेगा। उसने अपने सुझाव में यह भी कहा है कि शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत है और शिक्षा बजट जीडीपी का छह फीसद किया जाना आवश्यक है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से राज्यों की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जारी पहली परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2017-18 रेखांकित करती है कि शिक्षा की पहुंच के मामले में देश लक्ष्य से कोसों दूर है। रिपोर्ट में देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स देश के अन्य राज्यों मसलन, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली से नीचे है। इंडेक्स में गुजरात, चंडीगढ़ और केरल के स्कूलों का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सत्तर बिंदुओं के पैमाने पर आधारित परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी पीजीआइ रिपोर्ट को 2018 से तैयार करने की शुरुआत की है। मंत्रालय ने इन बिंदुओं के आधार पर सभी राज्यों से ऑनलाइन जानकारी मांगी थी और उनकी सूचना पर रिपोर्ट तैयार की गई। गौरतलब है कि राज्यों की शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन को छह अंकों में विभाजित किया गया था, जो कि 1000 से 551 मूल्यांकन पर आधारित था। इसमें कोई राज्य शामिल नहीं हो सका है, क्योंकि उनकी परफारमेंस 1000-851 वेटेज के मानकों को पूरा नहीं करती। चंडीगढ़, गुजरात और केरल को 801-851 का वेटेज या ग्रेड एक की श्रेणी मिली है। हरियाणा और पंजाब को 751-800 वेटेज के साथ ग्रेड दो, हिमाचल और उत्तराखंड को ग्रेड तीन संग 701-750 वेटेज और जम्मू-कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश को ग्रेड पांच के साथ 601-650 का वेटेज मिला है। ऐसे में इन आंकड़ों से समझना कठिन नहीं है कि देश में शिक्षा की हालत कितनी बदतर है।

इसके पहले भी अन्य कई रिपोर्टों में बदतर शिक्षा व्यवस्था का उल्लेख हो चुका है। शिक्षा की हालत कितनी जर्जर है, यह इसी से समझा जा सकता है कि देश के प्राथमिक विद्यालयों के तिरपन फीसद से अधिक बच्चे दो अंकों वाले घटाने के सवाल हल नहीं कर पाते। आधे से अधिक बच्चे गणित में बेहद कमजोर हैं। पांचवीं के अस्सी फीसद छात्र दूसरी कक्षा के पाठ सही तरीके से पढ़ नहीं पाते। आठवीं के बच्चे जोड़-घटाना और भाग तक नहीं जानते। सत्तर फीसद बच्चों को अंकों की पहचान नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र की एजुकेशनल फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग 2013-14 की एक रिपार्ट में कहा गया था कि भारत में निरक्षर युवाओं की तादाद तकरीबन अठाईस करोड़ सत्तर लाख है। यह आंकड़ा दुनिया भर के निरक्षर युवाओं की कुल तादाद का तकरीबन सैंतीस फीसद है। हालांकि रिपोर्ट में शिक्षा की बदहाली के कई कारण गिनाए गए, लेकिन शिक्षा पर होने वाले खर्च में भारी असमानता को सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया। मसलन, केरल में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च लगभग बयालीस हजार रुपए है, वहीं बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में छह हजार या इससे भी कम है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में गरीबी के कारण सत्तर फीसद और मध्यप्रदेश में पचासी फीसद गरीब बच्चे पांचवी तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि देश में शिक्षा का अधिकार कानून तथा सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद लाखों बच्चे स्कूली शिक्षा की परिधि से बाहर हैं। 2014 में कराए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार छह से चौदह साल के आयु वर्ग में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या 60.64 लाख थी। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से भी उद्घाटित हुआ कि भारत 2030 तक सबको शिक्षा देने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा।

आज देश में छह करोड़ ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा सुविधाएं हासिल नहीं हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या 1.11 करोड़ है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। इसी तरह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से वंचित विद्यार्थियों की तादाद 4.68 करोड़ है। यह स्थिति तब है, जब देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू है और सर्व शिक्षा अभियान पर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। गत वर्ष पहले प्रकाशित मानव संसाधन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोलह फीसद बच्चे बीच में ही प्राथमिक शिक्षा और बत्तीस फीसद बच्चे जूनियर हाईस्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि साठ फीसद छात्र तीसरी कक्षा उत्तीर्ण करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों में इस आयु वर्ग के बौद्ध और नवबौद्ध समुदायों के

18.2 फीसद, जैन 12.4 फीसद, सिख 23.3 फीसद, ईसाई 25.6 फीसद, हिंदू 25.9 फीसद तथा मुसलिम समुदाय के चौंतीस फीसद बच्चे प्री-स्कूल शिक्षा से वंचित हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के बावन फीसद बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं, जबकि 26.9 फीसद बच्चे पूर्व शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसी तरह निर्धनतम परिवारों के 51.9 फीसद बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं तथा 34.9 फीसद बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

तकनीकी शिक्षण संस्थानों का हाल भी बेहद चिंताजनक है। हर वर्ष साठ हजार भारतीय छात्र इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों का रुख कर रहे हैं। एक वक्त था, जब इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला हर छात्र यही चाहता था कि उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आइआइटी में दाखिला मिले। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में युवाओं की सोच में बदलाव आया है और उनकी नजर में अब आइआइटी को लेकर पहले जैसा आकर्षण नहीं है। इसके लिए संस्थानों में शिक्षकों का अभाव और संसाधनों की भारी कमी मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पिछले दिनों उद्योग संगठन एसोचैम के एक अध्ययन में कहा गया कि शिक्षा में सुधार की रफ्तार अगर ऐसी ही रही, तो भारत को विकसित देशों की तरह अपनी शिक्षा के स्तर को शीर्ष पर ले जाने में एक सौ छब्बीस साल का समय लगेगा। उसने अपने सुझाव में यह भी कहा है कि शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत है और शिक्षा बजट जीडीपी का छह फीसद किया जाना आवश्यक है। अगर बजट बढ़ता है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ी प्रतिभा का स्रोत वाला देश बनेगा।

पिछले साल प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों के दरम्यान स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 4.9 से बढ़ कर 5.3 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश के केवल सैंतीस फीसद बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सोलह लाख 12 हजार 285 लाख बच्चे ऐसे हैं, जो स्कूल नहीं जाते। यही हाल देश के अन्य राज्यों का भी है।

दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह भी है कि देश में तकरीबन बीस फीसद शिक्षक योग्यता मानकों के अनुरूप नहीं हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों में छह लाख शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। बिहार में 1.90 लाख और उत्तर प्रदेश में 1.24 लाख शिक्षक जरूरी योग्यता नहीं रखते। छत्तीसगढ़ में पैंतालीस हजार और मध्यप्रदेश में पैंतीस हजार अप्रशिक्षित शिक्षकों के भरोसे काम चलाया जा रहा है। ऐसी ही समस्या से झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम समेत अन्य राज्य भी जूझ रहे हैं। जबकि शिक्षा अधिकार कानून में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान है। अक्सर शिक्षकों के शिक्षण संस्थानों से गायब रहने की खबरें सुर्खियां बनती हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2006-07 में केंद्र सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे में प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ 81.07 फीसद और 2012-13 में 84.3 फीसद ही शिक्षक उपस्थित मिले। यानी पंद्रह से बीस फीसद शिक्षक शिक्षा परिसर से गायब रहे। उसी का कुपरिणाम है कि बच्चों को समुचित शिक्षण लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे पढ़ाई में बेहद कमजोर हैं।

तरु की छाया में

प्रयाग शुक्ल

दुनिया मेरे आगे

गरमी का मौसम आते ही तपती दोपहरियों में सभी किसी न किसी छाया की तलाश करते हैं- राही-बटोही, पशु-पक्षी, किसान-मयूर, रेहड़ी वाले। वे भी जो किसी साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार हों और थोड़ी देर का विश्राम चाहते हों। जो एयरकंडीशन गाड़ी में सवार हों और किसी वजह से वाहन खराब हो जाए, वे भी चाहते हैं कि किसी तरु की छाया मिल जाए थोड़ी देर के लिए। अक्सर यह छाया-तलाश किसी तरु-छाया की ही होती है। पत्तों से आच्छादित किसी घने, छायादार पेड़ की।

यह दृश्य भी आम है कि किसी हाइवे में दिख जाने वाले गांव-कस्बे-छोटे शहर का, जहां खुद उस गांव-शहर-कस्बे के लोग, दुकानदार हमें चारपाइयां डाले किसी घने तरु के नीचे दोपहरी बिता रहे होते हैं। पास ही पानी का एक घड़ा रखा होता है, अपने लिए भी और किसी परिचित-अपरिचित की प्यास बुझाने के लिए। गरमी का मौसम ही वह मौसम है, जो देश-भर में कमोबेश हर जगह अपना रंग दिखाता है। सर्दियों में अधिक ठंड पड़ने वाली जगहों से कुछ लोग उत्तर से दक्षिण की ओर चले जाते हैं। लेकिन गरमी तो उत्तर से भी अधिक दक्षिण को गरमा देती है- आंध्र और तमिलनाडु को। सभी तपते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। कुछ पहाड़ी जगहें जरूर ताप से बच जाती हैं।

अब तो फिर भी यातायात के साधन बढ़े हैं और लोग बस, टेंपो, ऑटो-रिक्शा आदि से अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन एक जमाना था हमारे बचपन का जब पैदल या बैलगाड़ियों से दस-बीस मील की यात्रा भी लंबी हुआ करती थी। पर जाना तो कई जगह दस-बीस मील से भी अधिक बैलगाड़ियों से ही होता था। हम गरमी की छुट्टियों में कलकत्ता (अब कोलकता) से अपने गांव आते, पुरखों के गांव, उत्तर प्रदेश में और ननिहाल भी जाते जो हमारे गांव से कोई बीस किलोमीटर तो होगा ही। जाना बैलगाड़ी से होता था। वह रास्ता लंबा लगता। हम पानी पीने के लिए किसी कुएं के पास रुकते। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करते। घने पेड़ों की छाया मिल जाती तो बैलगाड़ी वहीं खड़ी कर देते। बैलों को भी विश्राम मिलता।

पेड़ों की ओर ध्यान हम सबका यों भी जाता है, पर जब सघन छाया की तलाश हो, तब तो हम मानो उन्हें परखने भी लगते हैं। यानी यह नहीं, वह वाला। उसकी छाया अधिक घनी मालूम पड़ रही है... आदि। 'तरु छाया' की इस 'माया' और मनोहरता का कितना सुंदर चित्र खींचा है त्रिलोचन जी ने अपनी कविता 'कठफोड़े ने मार मार कर' में- 'आने वाले ग्रीष्म दिवस तरु की छाया में बीतेंगे, हर खोज, वहां मेला उमड़ेगा, नर-नारी आबाल वृद्ध चल कर आएंगे हरियाली में आप, ठहर कर इस माया में रमे रहेंगे और सीस पर से उखड़ेगा चिंता का संसार, विहग दल में गाएंगे।' यह कविता 1962 में लिखी गई थी।

तब से अब तक बिहग-दल कम हुए हैं। पेड़ भी बहुत कटे हैं। हमारे तरु-सम्मान में कुछ कमी आई है। बहुमंजिला फ्लैटों की कतारें, शहरों से बाहर निकल कर पेड़ों की छाया को दूर और दूर करती गई हैं। लेकिन नहीं, लोग चेते भी हैं। वृक्षारोपण का सिलसिला कई जगहों पर बना है। पद्मश्री से सम्मानित हुई एक सौ सात साल की कन्नड़ की वृक्ष-माता थिमक्का के बारे में लोगों ने जाना है, जिन्होंने कोई आठ हजार पेड़ अकेले दम पर लगाए हैं।

कई संस्थाओं ने समारोहों में स्वागत-सम्मान के अवसर पर भेंट दिए जाने वाले फूलों के गुच्छे की जगह पौधे उपहार में देने की सुंदर नीति अपनाई है। इस देश के भूगोल, उसकी जलवायु और उसकी ग्रीष्म-ऋतु की मांग भी यही है कि उसके पौधों और वृक्षों की संख्या में बढ़ोतरी हो। कई तरह का 'ताप' झेल रहे किसानों को आज भी हर हालत में चाहिए तरु-छाया। खेतों के निकट... राह में...। त्रिलोचन जी ने ही एक सुंदर चित्र रचा है खेतिहर-किसानों, मजदूरों का तरु-छाया के प्रसंग से अपनी चर्चित कविता 'मिल कर वे दोनों प्रानी दे रहे खेत में पानी' में। यह बहुतों को बहुत प्रिय है। इसका अंतिम पद है- 'विश्राम जरा करने को/ आराम जरा करने को/ नव कर्म-शक्ति भरने को/ आए हैं तरु-छाया में/ अपनी थकान हरने को/ मिल कर वे दोनों प्रानी/ दे रहे खेत में पानी।'

कल्पना की गई है, रचा भी गया है राहों को इस तरह कि उनके किनारे पेड़ हों और जरूरत पड़ने पर लोग उनकी छाया का लाभ उठा सकें। भला कौन नहीं चाहता अपनी किसी बस या ट्रेन यात्रा में या अपनी कार-बाइक-साइकिल यात्रा में कि यात्रा समाप्त होने तक दिखते रहें पेड़, खासकर ग्रीष्म ऋतु में। वे दूर से भी आंखों को ठंडक पहुंचाते। और न भूलें कि पशु ग्रीष्म में तरु-छाया को एक बड़ा आश्रय-स्थल मानते हैं। उसके नीचे बैठे-खड़े वे भी मानो असीस रहे होते हों तरु-छाया को।

तो बनी रहे तरु छाया। मिले इस ग्रीष्म में उन सबको, कहीं न कहीं जब वे तलाश रहे हों उसे।

खेलों से दूर

जब से बच्चों पर जिंदगी जीने से ज्यादा अधिक अंक लाने का दबाव बढ़ने लगा है तब से उनकी जिंदगी तनावपूर्ण हो गई है। परंपरागत खेलों के लिए अब बच्चों के जीवन में कोई जगह शेष नहीं रह गई है। लकड़ी, मिट्टी, कागज और पत्थर से बने खिलौने हमें अपने परिवेश से जोड़ते हैं। लेकिन अफसोस कि उनसे अब कोई नहीं खेलता। वे दिन लद गए जब बच्चे लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा... सुनकर बड़े होते थे। आज उनकी जिंदगी की शुरुआत स्मार्टफोन या ए फार एपल और बी फॉर बाल से होती है। जिन पंच तत्त्वों से मिल कर मानव शरीर बना है उनसे जुड़े खेल-तमाशे जब तक जिंदगी का हिस्सा रहेंगे तब तक तो जीवन ऊर्जा पाता रहेगा लेकिन जिनकी जिंदगी बंद कमरे में इंटरनेट के ब्लू व्हेल गेम, कार्टून के कृत्रिम खेल और वीडियो के आधुनिक खेलों में सिमट कर रह गई है उन्हें जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा आखिर मिले तो कहां से! ये खेल बच्चों के जीवन का विकास के बजाय विनाश कर रहे हैं।

अब गुब्बारे, बांसुरी, सीटी, गिल्ली-डंडा, चौपड़, शतरंज, नट के खेल देखने को नहीं मिलते। ये पारंपरिक खेल-खिलौने जीवन को परिवेश और श्रमशीलता से जोड़ते हैं। लकड़ी के खिलौने जहां काष्ठकला के हुनर को बढ़ावा देते हैं वहीं पत्थरों पर की गई नक्काशी पाषाण कला से परिचित कराती है। मिट्टी के खिलौने जहां माटी कला के हुनर की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं वहीं कठपुतलियों के करतब राजस्थान के कलाकौशल की बानगी की झलक प्रस्तुत करते हैं। केरल में नृत्य करती लकड़ी की गुड़िया, आंध्र में नव विवाहित जोड़ों की मूर्तियां, बंगाल में लकड़ी के देवी-देवता बनाने का प्रचलन है। ये पारंपरिक खेल-खिलौने रचनात्मकता के साथ-साथ अलग-अलग प्रदेशों के कला-कौशल को भी दर्शाते हैं। जापान और अन्य देशों में हानिकारक प्लास्टिक के बजाय कागज के खिलौनों के विकास पर जोर दिया जा रहा है जबकि हम अपने बच्चों को बचपन से ही मोटर, कार, बाइक, तोप, तमंचे, रिवाल्वर, रिमोट और एंड्रायड फोन की प्रतिकृति थमा कर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं?

देशी खेल-खिलौनों का बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास में अहम योगदान है। बच्चों को पारंपरिक खेल और परंपरागत खिलौनों से अलग करने का ही नतीजा है कि आज बच्चों से उनका बचपन छिनता जा रहा है। उनकी संवेदना और समझ में कमी आती जा रही है। स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में ही संभव है। संतुलित विकास के लिए खेलकूद आवश्यक है। खेल के मैदान के अभाव में शिक्षा से खेलों का महत्त्व घटता जा रहा है। ऐसे में बच्चों को खेलकूद से जोड़े रखने के प्रति अभिभावकों की जवाबदारी अहम हो जाती है। अनेक सर्वेक्षणों से यह बात साफ हो चुकी है कि निष्क्रिय बच्चों की तुलना में सक्रिय बच्चों में संज्ञात्मक कौशल का विकास तेजी से होता है। पारंपरिक खेल बच्चों में समूह संस्कृति और सामाजिक कौशल की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। इनसे उचित अंग विन्यास और मांस पेशियों के समुचित विकास को बढ़ावा मिलता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि खेलकूद से रक्त संचरण में होने वाले सुधार से बच्चों का हृदय संबंधी व्यायाम स्वतः ही हो जाता है। धैर्य, एकाग्रता, खिलाड़ी भावना, सहनशीलता, जीवन मूल्यों की समझ भी बच्चों में खेलों के कारण आती है। इसलिए बच्चे खेल रहे हैं यही पर्याप्त नहीं है, वे किस तरह के खेल खेल रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

● *देवेंद्र जोशी, उज्जैन*

विकल्प की ऊर्जा

देश के विकास के लिए अधिकाधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। बिजली पर हमारी बढ़ती निर्भरता के कारण भविष्य में ऊर्जा व्यय और भी बढ़ेगा। तो इतनी ऊर्जा आएगी कहां से? सब जानते हैं कि धरती पर कोयले और पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं, ये ज्यादा दिनों तक हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इनसे प्रदूषण भी होता है। लिहाजा, वैज्ञानिक लंबे समय से एक ऐसे ईंधन की खोज में हैं जो पर्यावरण और मानव शरीर को नुकसान पहुंचाए बगैर हमारी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने में सक्षम हो। वैज्ञानिकों की यह तलाश नाभिकीय संलयन (न्यूक्लियर फ्यूजन) पर समाप्त होती दिखाई दे रही है।

नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ही सूर्य और अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है। जब दो हल्के परमाणु नाभिक जुड़ कर एक भारी तत्त्व के नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। वैज्ञानिक कई वर्षों से सूर्य में संपन्न होने वाली संलयन क्रिया को पृथ्वी पर कराने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे बिजली पैदा की जा सके। अगर इसमें सफलता मिल जाती है तो यह सूरज को धरती पर उतारने जैसा होगा। हालांकि लक्ष्य अभी दूर है, मगर चीनी वैज्ञानिकों की इस दिशा में हालिया बड़ी सफलता ने उम्मीदें जगा दी हैं। चीन के हेफई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइंसेज के मुताबिक चीन अपने नाभिकीय विकास कार्यक्रम के तहत पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के जरिए सूर्य की तरह का एक ऊर्जा स्रोत बनाने का प्रयास कर रहा है।

● *मो सबीउद्दीन, पटना, बिहार*

प्रभावशाली जीत

कुछ हद तक विपक्षी एकता, सत्ता विरोधी रुझान, जातीय समीकरण, राफेल और रोजगार को मुद्दा बनाए जाने के बाद भी नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के दम पर लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत हुई है। यह प्रधानमंत्री पर जनता और भाजपा का भरोसा ही था कि एग्जिट पोल्स देख कर पार्टी ने सहयोगी दलों के लिए रात्रि भोज रखा जबकि समूचे विपक्ष में खलबली मची हुई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल जैसे राज्यों में भी मोदी मैजिक देखने को मिला है। प्रधानमंत्री को दुनियाभर के नामचीन राजनेताओं ने बधाई दी है। इनमें से उनके करीबी दोस्त कहे जाने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले इजराइली भाषा में ट्वीट किया और फिर थोड़ी देर बाद हिंदी में भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी आपके प्रभावशाली चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। ये चुनावी नतीजे एक बार फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपके नेतृत्व को साबित करते हैं।'

● *अमन सिंह, प्रेमनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com